EXCLUSIVE

NEWS ANALYSIS BY

Mr. Shridhant Joshi

कौटिल्य एकेडमी

कौटिल्य एकेडमी

सिंधु वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

GettyImages

भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया। उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। @स्पोर्ट्स

कौटिल्य एकेडमी

बैडमिंटन : छह फाइनल में लगातार हार के क्रम को तोड़ा भारतीय स्टार सिंधु ने

रचा इतिहास, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जीता खिताब

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

ग्वांग्झू. ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप की रजत विजेता भारत की पीवी सिंधु ने फाइनल में हारने की बाधा से आखिर मुक्ति पाते हुए साल के अंतिम बैडमिंटन टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रविवार को खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। सिंधु यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।

सिंधु ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की निजोमी ओकुहारा को एक घंटे दो मिनट में 21-19, 21-17 से हराकर खिताब जीता। सिंधु का 2018 में यह पहला खिताब है और इस तरह उन्होंने साल का समापन खिताब के साथ कर लिया। रैंकिंग में छठे नंबर की सिंधु ने पांचवीं रैंकिंग की ओकुहारा के खिलाफ अपना रेकार्ड अब 7-6 का लिया है। सिंधु ने इस जीत के साथ लगातार कई फाइनल हारने और चोकर्स के ठप्पे से मुक्ति पा ली है।

इन टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं मिली थी जीत

2016	रियो ओलंपिक
2017	विश्व चैंपियनशिप
2017	वर्ल्ड टूर फाइनल्स
2018	राष्ट्रमंडल खेल
2018	विश्व चैंपियनशिप
2018	जकार्ता एशियाई खेल

पिछली हार का बदला चुकाया

सिंधु पिछले साल इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में हार गई थीं लेकिन इस बार उन्होंने खिताब जीत कर ही दम लिया। सिंधु ने इस जीत का जश्न आंसुओं के बीच मनाया। उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। सिंधु ने ओकुहारा से पिछले साल विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार का हिसाब चुका लिया।

पहले गेम में सिंधु की शानदार शुरुआत

23 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी सिंधु ने मुकाबले में शानदार शुरुआत हुए 11-6 की बढ़त हासिल कर ली। ओकुहारा ने फिर वापसी करते हुए स्कोर को 15-13 कर दिया। कुछ देर बाद स्कोर 17-17 हो गया। लेकिन सिंधु ने संयम दिखाते हुए अंक लिए और स्कोर 20-19 पहुंचा दिया। सिंधु ने 21-19 पहला गेम जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में भी शानदार शुरुआत करते हुए 2-0 की बढ़त बना ली। दूसरे गेम में ब्रेक तक सिंधु ने 11-9 से आगे हो गईं। सिंधु ने जापानी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और दूसरा गेम 21-17 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।

शाबाश सिंधु

भारत के युवा खिलाड़ी जिस तरह देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उससे लगता है कि अगले ऑलम्पिक और विश्व खेलों में हमारी मैडल टेली में सुधार होगा।

भारतीय शटलर क्वीन पीवी सिंधु ने ग्वांग्झू में नया स्वर्णिम इतिहास रच दिया। सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में हार जाने का मिथक भी तोड़ दिया। सिंधु ऑलम्पिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों के अलावा विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। लेकिन इन सभी जगह उन्हें स्वर्ण के स्थान पर रजत-पदक पर ही संतोष करना पड़ा था। 2018 में भी सिंधु कोई खिताब नहीं जीत पाई थीं, लेकिन वर्ष का अंतिम माह उनकी झोली में स्वर्णिम खुशियां भर गया। फाइनल में भारतीय शटलर ने जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त नोजोमी ओकुहारा को कड़े मुकाबले में 21-19, 21-17 से हराया। विश्व में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु पूरी प्रतियोगिता में गजब फॉर्म में दिखीं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को परास्त कर खिताब जीतने के इरादे जता दिए थे। लेकिन अभी तक सिंधु के साथ अजीब संयोग जुड़ा था कि वह विश्व के जितने भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं सभी के फाइनल में तो पहुंच जाती थीं, लेकिन आखिरी मुकाम में डगमगा जाती थीं। सिंधु इस टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार तीसरी बार पहुंची। पिछली बार वे जापानी खिलाड़ी अकाने यामागूची से हार गई थीं।

सिंधु से पूर्व सायना नेहवाल भी 2011 में वर्ल्ड सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंची थीं जबकि ज्वाला गुट्टा और वी. डीजू की जोड़ी 2009 में उपविजेता रही थी। मानसिक संतुलन और शारीरिक दमखम के इस खेल में सिंधु ने फाइनल के आखिरी क्षणों में अपनी गति और लय बरकरार रखी और जापानी खिलाड़ी को आगे नहीं निकलने दिया। 5 जुलाई 1995 में जन्मीं पीवी सिंधु ने बैडमिंटन जगत में ऐसे समय में प्रवेश किया जबकि सायना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा जैसी खिलाड़ियों की तूती बोलती थी। अपनी कड़ी मेहनत और दमखम के बल पर सिंधु मात्र 17 वर्ष की आयु में विश्व महिला बैडमिंटन फेडरेशन की टॉप-20 खिलाड़ियों में शामिल हो गई थीं। 2016 में वे ऑलम्पिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनीं। इससे पूर्व सायना नेहवाल ही कांस्य पदक जीत पाई थीं। उनकी उपलब्धियां यहीं कम नहीं हुईं। 2017 और 2018 की विश्व चैम्पियनशिप में उन्होंने लगातार रजत पदक जीता। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।

भारत के युवा खिलाड़ी जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उससे लगता है कि अगले ऑलम्पिक और विश्व खेलों में हमारी मैडल टेली में सुधार होगा। खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ घोषणा भी कर चुके हैं कि 2030 तक हम खेलों में चीन, अमरीका, रूस और जापान जैसे देशों के मुकाबले में आ जाएंगे। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण और साजो-सामान की वह सुविधाएं अभी नहीं मिल पाईं जो कि उन्हें विश्व स्तर पर मुकाबले में खड़ा कर सकें। क्रिकेट में तो हम शीर्ष पर हैं, लेकिन उतनी ही शोहरत और सुविधाएं अन्य खेलों और खिलाड़ियों को मिलें तो हमारे खिलाड़ी किसी से पीछे न रहें। देश में कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल के क्षेत्र में भी क्रिकेट की तरह औद्योगिक घराने उतरने लगे हैं। हाल ही उड़ीसा में छह टॉप उद्योगों ने अलग-अलग खेलों को गोद लेकर नया अध्याय शुरू किया है। अन्य राज्यों और केन्द्र के स्तर पर भी इस तरह की व्यावसायिक भागीदारिता खेलों में लाई जाए, तो देश में खेलों का भविष्य स्वर्णिम होगा, इसमें कोई शक नहीं।

कौटिल्य एकेडमी

चीन के सामने राजनयिक संतुलन बनाने की चुनौती

जब से चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और उसने 2008 के ओलिंपिक गेम्स आयोजित किए उसके बाद से बीजिंग को वॉशिंगटन या दुनिया की किसी प्रमुख राजधानी से मदद नहीं मांगनी पड़ी है। लंबे समय से वृद्धि का स्रोत होने और वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान स्थिरता देने वाले प्रभाव के कारण चीन ने आमतौर पर मजबूती से समझौता वार्ताओं में भाग लिया है। अब शी के सामने वह लग्जरी नहीं है।

• किथ ब्रैडशेर, शंघाई ब्यूरो चीफ/कैथरीन पोर्टर

© The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने अब आर्थिक संकट के साथ राजनयिक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है। कनाडा में अमेरिका के कहने पर चीन की शीर्ष एग्जीक्यूटिव को हिरासत में लेने पर चीन ने संयमित प्रक्रिया ही दी है।

चीन के उपभोक्ता और बिजनेस का आत्मविश्वास घट रहा है। कारों की बिक्री में एकदम गिरावट आई है। हाउसिंग बाजार लड़खड़ा रहा है। कुछ फैक्ट्रियां कामगारों को दो माह बाद आने वाले चीनी नववर्ष की छुट्टियों पर अभी से भेज रही हैं। हाल के महीनों में चीनी अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जो शायद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनके सामने ऐसे कठिन विकल्प हैं, जो तेजी तो ला देंगे पर भारी कर्ज जैसी देश की दीर्घावधि समस्याएं बढ़ा देंगे। दुनिया के मंच पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रियायतें देने पर मजबूर होना पड़ा है।

इसका कितना बुरा असर उन पर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि यु हॉन्ग जैसे चीनी कामगारों के जॉब कितने तेजी से गायब होते हैं। हाल ही में एक दोपहर 46 वर्षीय यु हुबेई प्रांत के घर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। उन्हें करीब तीन माह की अवैतनिक छुट्टियों पर रवाना कर दिया गया था। दोनगुआन में वे जिस लैम्प फैक्ट्री में काम करते थे उसने वेतन और काम के घंटों में बहुत कटौती कर दी है। चीन के डेटा की विश्वसनीयता नहीं होने से आर्थिक गिरावट कितनी है, यह पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन, ऐसे संकेत हैं कि देश की समस्याएं गहरा रही हैं। शुक्रवार को चीन अधिकारियों ने रिटेल सेल्स और वैश्विक बाजार पर निर्भर औद्योगिक उत्पादन में कमजोर वृद्धि की जानकारी दी। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक दशक पहले की मंदी के बाद यह सबसे खराब गिरावट है। तब बीजिंग को वृद्धि को पटरी पर बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर झोंकने पड़े थे।

लंदन के एनोडो इकोनॉमिक्स की चीफ इकोनॉमिस्ट डायना चोयलेवा कहती हैं 'शी जिनपिंग ने चीन की तुलना समुद्र से की है, जिसे कोई तूफान विचलित नहीं कर सकता पर अब जो तूफान आया है वह अब तक का सबसे बड़ा है।' पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने चीनी नेतृत्व को बड़ा मंच दिया है। जब से चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और 2008 के ओलिंपिक गेम्स आयोजित किए उसके बाद से बीजिंग को वाशिंगटन या दुनिया की किसी प्रमुख राजधानी से मदद नहीं मांगनी पड़ी है। लंबे समय से वृद्धि का स्रोत होने और वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान स्थिरता देने वाले प्रभाव के कारण चीन ने आमतौर पर मजबूती से समझौता वार्ताओं में भाग लिया है। अब शी के सामने वह लग्जरी नहीं है। उन्होंने चीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन के साथ अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण और दृढ़ किया है। इस साल उन्होंने कार्यकाल संबंधी बाधाएं दूर कर ली हैं। अब चाहें तो आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं। जहां अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध अच्छा बहाना है पर लंबे समय तक गिरावट का दोष तो अंततः उन पर ही आएगा। सरकार ने पहले ही आदेश दिया कि बुरी आर्थिक खबरों को रोका जाए। अब शी के सामने राजनयिक संतुलन साधने की चुनौती भी है। कनाडा में अमेरिका के कहने पर चीन की शीर्ष एग्जीक्यूटिव को हिरासत में लेने के बदले में चीनी अधिकारियों ने दो कनाडाई नागरिकों को हिरासत में लिया है। लेकिन, गिरफ्तारियों पर चीन अधिकारियों ने अमेरिका के सामने नरम लहजा बनाए रखा है, क्योंकि ट्रेड वॉर में और तेजी से चीनी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ही फायदे की स्थिति भांप ली है। उन्होंने ट्वीट किया, 'चीन ने घोषणा की है कि उनके साथ हमारे व्यापार युद्ध के कारण चीनी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है।'

वह तो चीन सरकार का महत्वपूर्ण उद्योगों और फाइनेंशियल सेक्टर पर कड़ा नियंत्रण है तो मंदी की हालत में किसी अन्य देश की तुलना में इसके पास अधिक विकल्प हैं। बीजिंग के प्रयास उस कर्ज को कम करने में लगे थे, जो मंदी का कारण है पर अब प्रयास उलटे हो गए हैं। पहले ही सरकार ने सरकारी खर्च तेज कर दिया है, जिसने इकोनॉमी को भूतकाल में उबारा था। सरकार की दिग्गज कंपनी शीझोऊ कंस्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप कई हाईवे और रेल निर्माताओं को सप्लाई करती है। कंपनी के चेयरमैन वांग मिन बताते हैं, हमारी बिक्री एक साल की तुलना में 50 फीसदी बढ़ गई है।

नियामकों ने भी बैंकों से कहा कि वे प्राइवेट बिजनेस को अधिक उधार दें। मंत्रियों ने कंपनियों से वादा किया है कि वे कामगारों को न निकालें, उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। पर्यावरण संबंधी नियमों को शिथिल किया जा रहा है। इससे प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों का बना रहना आसान हो गया है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक वृद्धि में अगले साल के मध्य में सुधार होगा। ऐसा लगता है कि अब तक चीन वैश्विक आर्थिक संकट के दिनों की तरह नौकरियां जाने की संकट को टालने में कामयाब रहा है। लेकिन, अर्थव्यवस्था का दोहन करने के चीन के विकल्प उतने कारगर नहीं रहे हैं, जितने कभी हुआ करते थे। चीन में डिफाल्टरों की संख्या में छोटी लेकिन, उल्लेखनीय वृद्धि से ऋणदाताओं में घबराहट पैदा हो गई है।

कनाडा मुसीबत में

चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवेई की शीर्ष अधिकारी मेंग वानझाऊ की गिरफ्तारी पर कनाडा मुश्किल में फंस गया है। दोनों देश उसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार है और उसके सामने दोनों को खुश रखने की चुनौती है। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को नया रूप देने की बातचीत में जला कनाडा चीन के साथ मजबूत व्यापार संबंध चाहता है ताकि वह अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता घटा सके। कनाडा के कई लोग कनाडा को लेकर ट्रम्प के सतही दृष्टिकोण से चिंतित हैं। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन रिसर्च में सीनियर फेलो विनरान जियांग के मुताबिक कनाडा कुआं और खाई की स्थिति में फंस गया है। उसने मेंग को जमानत पर रिहा किया पर उससे चीन संतुष्ट नहीं हुआ। वह तत्काल रिहाई चाहता है। कनाडा ने अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि की दुहाई दी है पर उससे चीन और ख़फा हो गया है।

कौटिल्य एकेडमी

प्रयासः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष आयोजित हो रहे कुंभ में आवागमन को सुचारू बनाने की कवायद शुरू

कुंभ मेले में अंतर्देशीय जलमार्गों पर जोर!

एनडीए सरकार ने 15 जनवरी से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले के दौरान लोगों और सामान के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सरकार की जल परिवहन शाखा, इनलैंड वॉटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आइडब्ल्यूएआइ), 2019 में आयोजित हो रहे इस उत्सव के लिए यात्री परिवहन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रही है। कुंभ के मेले में आने वाली तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पर्याप्त बंदोबस्त हो रहे हैं।

फाइल फोटो

कुंभ मेले के दौरान भारी तादाद में आने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागन की सुविधा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में कई उपाय आजमाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (प्रयागराज से हल्दिया) के विकास के हिस्से के रूप में, आइडब्ल्यूआइ गंगा नदी के प्रयागराज-वाराणसी स्ट्रेच को नेविगेट करने के लिए पर्याप्त हस्तक्षेप कर रहा है। इस संबंध में, आइडब्ल्यूआई, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच गंगा नदी में समूचे चैनल के लिए एक मीटर का पर्याप्त तलछट उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। यह जहाजों का एक निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा।

लाखों तीर्थयात्रियों का जुड़ाव

कुंभ मेला एक धार्मिक हिंदू तीर्थयात्रा है, जिसे 12 साल के दौरान चार बार मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार सबसे बड़ा कुंभ और छह वर्ष में एक बार अर्द्धकुंभ होता है। भौगोलिक क्षेत्र चार जगहों पर फैला हुआ है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और महाराष्ट्र। यह त्योहार धार्मिक तीर्थयात्रियों के सबसे बड़े जुड़ाव के रूप में जाना जाता है और लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्री गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करते हैं। 2013 में अनुमानित तौर पर 12 करोड़ लोग महाकुंभ में गए थे। महा कुंभ हर 144 वर्षों में एक बार होता है।

कुंभ के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा सरकार की प्राथमिकता में है। नवंबर में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा था कि शीर्ष रूसी कंपनियों के हाइब्रिड एरोबोट्स को कुंभ में यात्रियों के परिवहन के लिए शामिल किया जा सकता है, इससे संबंधित पायलट परियोजना शुरू हो सकती है।

चार फ्लोटिंग टर्मिनल के बीच फेरी लगाएंगे दो जहाज!

आइडब्ल्यूएआइ के उपाध्यक्ष प्रवीर पांडे का दावा है, 'इनलैंड वॉटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमेशा बड़े तीर्थ के दौरान सुरक्षित और आरामदायक परिवहन की दिशा में योगदान दिया है। कुंभ मेले में दी जा रही सुविधाएं महत्त्वपूर्ण साबित होंगी और मेला अथॉरिटी की मदद करेंगी। अतीत में, हमने पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला और पटना में प्रकाश पर्व में हमारे जहाजों से मदद की है और चैनल चिह्नित किए हैं।' सरकार की जल परिवहन शाखा ने चार फ्लोटिंग टर्मिनलों की स्थापना की है, किलाघाट, सरस्वती घाट, नैनी ब्रिज और सुजवान घाट, प्रत्येक में एक टर्मिनल। आइडब्ल्यूएआइ ने एक बयान में बताया है कि सीएल कस्तूरबा और एसएलकेमला जैसे दो जहाजों को तीर्थयात्रा के लिए तैनात किया जाएगा।

हाइब्रीड एरोबोट्स पर भी विचार

प्रयागराज और वाराणसी के बीच एक फेयर वे या डीपवॉटर चैनल को बनाया जाएगा। वहीं, छतनाग, सिरसा, सीतामढ़ी, विंध्याचल और चुनार में पांच अस्थायी जेटी भी यात्रियों जहाज तक लाने और ले जाने के तैयार रहेंगी। आइडब्ल्यूआइ के बयान में कहा गया है कि आइडब्ल्यूआइ के पास अंतर्देशीय नेविगेशन के माध्यम से परिवहन के सुरक्षित और कुशल तरीके प्रदान करने का जनादेश है। राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (प्रयागराज से हल्दिया) के विकास के हिस्से के रूप में, आइडब्ल्यूआइ गंगा नदी के प्रयागराज-वाराणसी स्ट्रेच में नौकायन के लिए पर्याप्त हस्तक्षेप कर रहा है। बीते नवंबर में, परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार कुंभ मेले के दौरान वैकल्पिक परिवहन मोड के लिए हाइब्रीड एरोबोट्स पर विचार कर रही है।

नदियों के प्रदूषण व जूट पर ध्यान खींचने के लिए बांस की नाव!

नदी प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और जूट जैसी पर्यावरण हितैषी सामग्रियों के महत्त्व को कायम रखने के लिए पश्चिम बंगाल के आठ युवाओं ने एक अनूठी पहल करते हुए जूट और बांस से बनी नाव में गंगा पर 213 किलोमीटर का जोखिम भरा सफर पूरा किया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हलदेया से 7 दिसंबर को शुरू हुई नौ दिन की लंबी यात्रा बंगाल के हावड़ा शहर में पूरी हुई। यात्रा के अगुवा पुष्पेष सामंत के अनुसार यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद, 39 फीट लंबी और छह फीट ऊंची नाव की एक जहाज से टक्कर होते-होते बची। सामंत के अलावा, आशीम मंडल, विश्वजीत मोंडल, अरशद अली मंडल, हसीम अब्दुल हलीम, मोमिन अली मंडल, अमीर हुसैन जमदार, विशाल गोयल ने यात्रा में हिस्सा लिया। घटना के कुछ दिनों के भीतर, उन्हें एक और दुर्घटना का सामना करना पड़ा ,जब मजबूत धाराओं ने नाव को लगभग डुबोने की तैयारी कर ली थी।

जल्द ही उड़ान के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे अपने फोन से इंटरनेट

जल्द ही भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर हवाई यात्रा के दौरान लोग अपने फोन के माध्यम से कॉल और इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे क्योंकि सरकार ने ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। भारतीय और विदेशी एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां वैध भारतीय दूरसंचार लाइसेंस धारक के साथ साझेदारी में इन-फ्लाइट और समुद्री आवाज और डेटा सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। 14 दिसंबर के अधिसूचना पत्र में कहा गया है कि 'इन नियमों को उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी नियम, 2018 कहा जा सकता है। वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख पर लागू होंगे।' इन-फ्लाइट एंड मेरटाइम कनेक्टिविटी (आइएफएमसी) को जमीन पर दूरसंचार नेटवर्क के साथ-साथ उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान किया जा सकता है। कहा गया है कि सेवाओं को अंतरिक्ष विभाग की अनुमति से घरेलू और विदेशी उपग्रहों के जरिए भारत में वैध दूरसंचार लाइसेंसधारक को प्रदान किया जा सकता है। 'आइएफएमसी प्रदान करने के लिए उपग्रह प्रणाली का उपयोग करने के मामले में, टेलीग्राफ संदेश भारत के भीतर स्थित सैटेलाइट गेटवे अर्थस्टेशन स्टेशन के माध्यम से गुजारा किया जाएगा... और ऐसे उपग्रह गेटवे अर्थस्टेशन एनएलडी या सूचना के आगे वितरण के लिए आईएसपी लाइसेंसधारक के नेटवर्क की पहुंच सेवा से जुड़े हुए होंगे।

कौटिल्य एकेडमी

वर्ष 2022 में जी-20 समिट की मेजबानी करेगा भारत

दुनिया के कारोबार का 80% हिस्सा इन 20 देशों के पास

भारत 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उस साल देश की आजादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। जी-20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। पहले वर्ष 2022 में जी 20 सम्मेलन की मेजबानी इटली को करनी थी, लेकिन अब भारत इसका मेजबान बनेगा। जानें इस संगठन से जुड़ी बातें।

आमतौर पर जिसे जी-20 कहा जाता है, उसका मतलब है 'ग्रुप ऑफ 20'। यह एक ऐसा समूह जिसमें 19 देश हैं और 20वां हिस्सेदार है यूरोपीय संघ। सभी भागीदार साल में एक बार इस शिखर सम्मेलन में एक दूसरे से मिलते हैं। इन बैठकों में राज्यों के सरकार प्रमुखों के साथ उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यहां यूरोपीय आयोग करता है। साथ ही यूरोपीय केंद्रीय बैंक भी बैठक में हिस्सा लेता है। मुख्य रूप से यहां आर्थिक

अहमियत रखते हैं समूह के फैसले

हालांकि इन देशों की मुलाकात अनौपचारिक होती है, लेकिन जी-20 के देश जो फैसला लेते हैं, उसमें वजन होता है। दुनिया के 20 औद्योगिक और विकासशील देश वैश्विक उत्पादन के 90 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह वे अंतरराष्ट्रीय कारोबार, वैश्विक विकास और जलवायु परिवर्तन को भी काफी प्रभावित करते हैं। जी-20 का गठन जी-7 देशों ने किया है।

10 साल पहले अस्तित्व में आया नया स्वरूप

जी-8 को राजनीतिक और जी-20 को आर्थिक मंच के तौर पर अलग अलग पहचान दी गई। 2014 में रूस को जी-8 से अलग किया गया और वह एक बार फिर जी-7 बन गया। आज जिस रूप में हम जी-20 को जानते हैं, उसकी शुरुआत 10 साल पहले नवंबर 2008 से हुई। अमेरिका में पहली बार 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आर्थिक मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। 2009 और 2010 में यह बैठक दो बार हुई। दुनिया में जी संगठनों की सूची लंबी है।

कैसे हुई इस संगठन की शुरुआत

जी-20 को समझने के लिए जी-7 के बारे में जानकारी जरूरी है। 1975 के आर्थिक संकट के मद्देनजर दुनिया के छह बड़े देशों ने एकसाथ आने का फैसला किया। ये देश थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। एक साल बाद कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और इस तरह से जी-7 की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद धीरे-धीरे रूस को इस समूह में शामिल करने के प्रयास शुरू किए गए। 1998 में आखिरकार रूस भी जुड़ गया और समूह जी-7 से जी-8 बन गया। इसके अगले ही साल जून 1999 में जब जर्मनी के कोलोन शहर में जी-8 देशों की बैठक हुई, तब एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा की गई। उस वक्त दुनियाभर की 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को एकसाथ लाने का फैसला किया गया। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार जी-20 का रास्ता तय करने के लिए बैठक हुई। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने शिरकत की। माना जाता है कि बीस देशों की सूची बनाने का काम जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर किया था। वक्त के साथ बैठक के रूप में कई बदलाव आए। आज जी-20 जिस स्वरूप में खड़ा है, उसके पीछे संगठन का कई वर्षों का उतार-चढ़ाव शामिल है।

इन 20 देशों में रहती है दुनिया की दो तिहाई आबादी

यूरोपीय संघ के अलावा ये 19 देश जी-20 के सदस्य हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया के सकल उत्पाद यानी जीडीपी का 85 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा इन देशों के वैश्विक व्यापार में हिस्सा भी 80 फीसदी है। यही नहीं, दुनिया की दो तिहाई आबादी यहीं रहती है। जी-20 की बैठक के दौरान कुछ 'मेहमानों' को भी आमंत्रित किया जाता है। अफ्रीकी संघ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (एपेक), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व बैंक, विश्व आर्थिक संगठन (डब्ल्यूटीओ) और स्पेन इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले स्थाई अतिथि हैं।

आखिर क्यों खास है यह संगठन?

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे आर्थिक विवाद को देखते हुए जी-20 जैसे मंच की अहमियत समझ में आती है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से कई तरह के बदलाव आए हैं। अपनी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत ट्रंप ने जी-20 के उसूलों को कई बार नजरअंदाज किया है। वे लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं और उन्होंने यह कहने में भी कभी संकोच नहीं जताया है कि उनके लिए सिर्फ उन्हीं के देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है।

इन संगठनों की है अलग भूमिका

जी-15

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपना असर बढ़ाने के लिए 1989 में 15 विकासशील देशों ने एक समूह का गठन किया। अब इस समूह में 17 सदस्य हैं और वे 2 अरब की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसी सहयोग के जरिए दक्षिण और दक्षिण के बीच विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।

जी-77: गरीबों का ग्रुप

सिर्फ धनी देश ही यूएन में वैश्विक आर्थिक नीति पर फैसला न करें, इसलिए विश्व व्यापार सम्मेलन में 77 विकासशील देशों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इस समय जी-77 में 134 सदस्य हैं, लेकिन उनका असर अभी भी मामूली है। इसके दो बड़े सदस्य भारत और चीन जी-20 के भी सदस्य हैं।

कौटिल्य एकेडमी

Fresh Prescription

13 economists push a grounded debate on India's agrarian and job crises

Two issues were common to states which went to polls recently: agrarian and job crises. Both recur at intermittent intervals, suggesting that political parties, regardless of their stripe, haven't found durable solutions. In this context, a non-partisan effort by a group of economists from academia and private sector to put together a concise strategy paper is welcome. Titled 'An Economic Strategy for India', it identifies the main challenges and suggests some solutions. It seeks to trigger a grounded debate on economic issues. In the run-up to the next general election this is urgently needed.

The 13 economists, including Raghuram Rajan and IMF's chief economist Gita Gopinath, do not represent a single ideological persuasion. Therefore, when they point out that farm loan waivers, the staple of an election manifesto today, do not work, it's time to reconsider it as the default solution. States have tried experiments in an effort to reform, most notably with Telangana providing an upfront investment support. These are sensible practices which can be replicated across other states. Other suggestions, which have often come from within governments, to reduce the monopoly power of middlemen and clear obstacles to competition in the supply chain also make sense.

India is at a crossroads when it comes to its youth. In the absence of opportunities, a potential demographic dividend can turn into a nightmare. Two aspects were picked by the paper for special mention. Labour contracts need more flexibility to accommodate different kinds of needs on both sides. This may play an important role in attracting some of the spillover investment triggered by companies trying to hedge their exposure to China on the heels of a trade war. Separately, education is an area which needs intense government engagement but without baggage.

Environmental pollution and healthcare gaps blight the quality of life for the average Indian but they have been relegated to the periphery by political parties. It's not too late to improve performance in these areas to improve the quality of living. In the run-up to the next Lok Sabha election, as parties launch into campaign mode and also prepare manifestos, hopefully this effort will allow Indian citizens to ask more meaningful questions on their economic strategy. This is essential because it's apparent differences in economic strategies of political parties are superficial. Repeating bad ideas run the risk of transforming a jobs crisis into a social crisis.

कौटिल्य एकेडमी

10 REASONS WHY FARMERS ARE IN DISTRESS

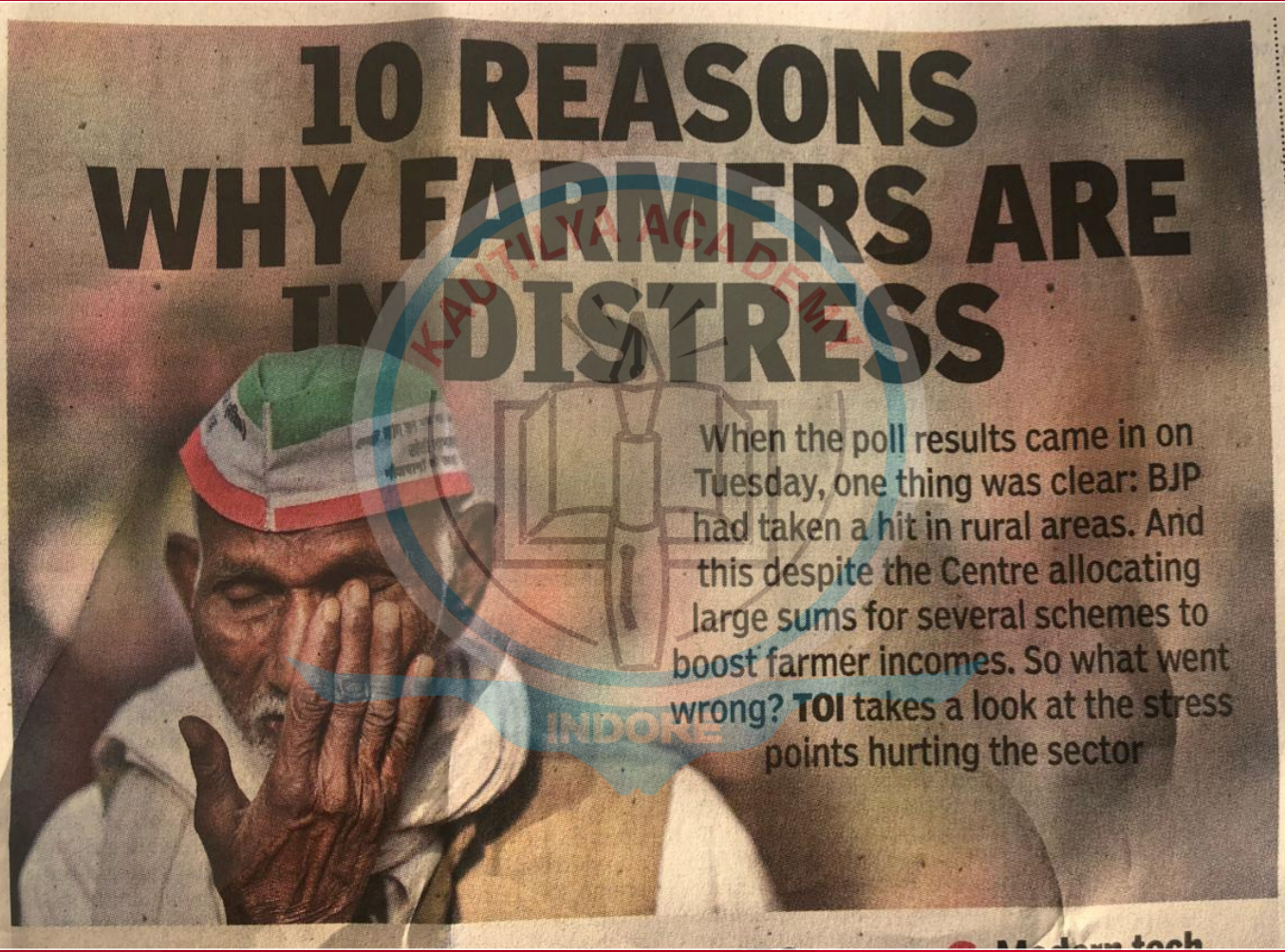

When the poll results came in on Tuesday, one thing was clear: BJP had taken a hit in rural areas. And this despite the Centre allocating large sums for several schemes to boost farmer incomes. So what went wrong? **TOI** takes a look at the stress points hurting the sector

KAUTILYA ACADEMY INDORE

कौटिल्य एकेडमी

1 Two years of drought

Two successive years of drought (2014, 2015) have taken a toll on the farm sector. The government has allocated significant funds for the sector but slow implementation of projects has not eased the pain. Drought in Maharashtra, Gujarat and Karnataka have also added to farmers' woes

कौटिल्य एकेडमी

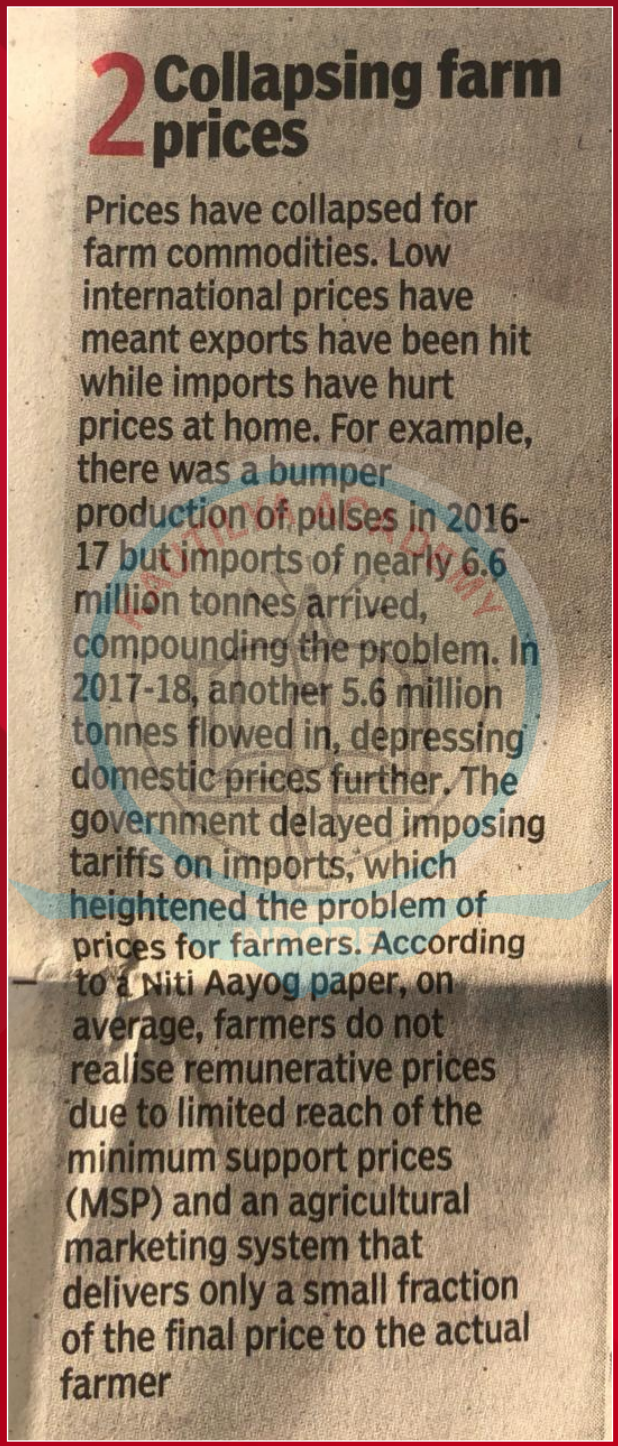

2 Collapsing farm prices

Prices have collapsed for farm commodities. Low international prices have meant exports have been hit while imports have hurt prices at home. For example, there was a bumper production of pulses in 2016-17 but imports of nearly 6.6 million tonnes arrived, compounding the problem. In 2017-18, another 5.6 million tonnes flowed in, depressing domestic prices further. The government delayed imposing tariffs on imports, which heightened the problem of prices for farmers. According to a Niti Aayog paper, on average, farmers do not realise remunerative prices due to limited reach of the minimum support prices (MSP) and an agricultural marketing system that delivers only a small fraction of the final price to the actual farmer

कौटिल्य एकेडमी

3 Insurance fails to serve

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched in 2016 to provide insurance and financial support to farmers in the event of failure of any crops due to natural calamities, pests and diseases. It was also meant to stabilise the income of farmers and ensure they remain in farming. But the scheme has seen lower enrolments due to a string of factors, including high premiums and lack of innovation by insurance firms

कौटिल्य एकेडमी

4 Irrigation takes a hit

Irrigation is crucial for the farm sector, where large tracts of land still depend on monsoon rains. The Centre launched the Rs 40,000-crore Long-Term Irrigation Fund, operated by the National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard). Under this programme, 99 large irrigation projects were to be completed by December 2019 but the progress so far has been limited. Experts say a number of factors, including bureaucratic delays and slow implementation by states, have hurt progress for this crucial input

कौटिल्य एकेडमी

5 Marketing is ignored

According to a Niti Aayog document, farm sector development has ignored the potential of marketing. Archaic laws still hobble the sector. Access of farmers to well-developed markets remains an issue although several initiatives have been launched to develop an electronic market place. Reforms to the APMC Act have been slow and most states have dragged their feet on it. Experts suggest an entity such as the GST Council to bring together states and the Centre to jointly take decisions to reform the sector and provide better access to markets for farmers. According to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the combination of market regulations and infrastructure deficiencies leads to a price depressing effect on the sector

कौटिल्य एकेडमी

6 Modern tech missing

Introduction of latest technology has been limited due to a number of reasons. Access to modern technology could act as a boost to productivity through improved variety of seeds, farm implements and farming technology. According to a Niti Aayog paper, there has been no real technological breakthrough in recent times

कौटिल्य एकेडमी

7 Fragmented supply chains

Large gaps in storage, cold chains and limited connectivity have added to the woes of farmers. It has also added to the significant post-harvest losses of fruit and vegetables, estimated at 4% to 16% of the total output, according to the OECD

कौटिल्य एकेडमी

8 Lack of food processing clusters

This has meant that there is little incentives for farmers to diversify. According to an OECD document, share of high-value sectors in food processing is low with fruit, vegetable and meat products accounting for 5% and 8% of the total value of output compared to cereal-based products at 21% and oilseeds at 18%

कौटिल्य एकेडमी

9 Delayed FCI reforms

A government-appointed panel had recommended that FCI hand over all procurement operations of wheat, paddy and rice to states that have gained sufficient experience in this regard and have created reasonable infrastructure for procurement. These states are Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Madhya Pradesh. It had suggested a complete overhaul of FCI and recommended that farmers be given direct cash subsidy (of about Rs 7000/ha) and fertiliser sector deregulated. The panel had said direct cash subsidy to farmers will go a long way to help those who take loans from money lenders at exorbitant interest rates to buy fertilisers or other inputs, thus relieving some distress in the agrarian sector. The report has been put in cold storage

कौटिल्य एकेडमी

10 Low productivity

The share of the farm sector in GDP has declined from 29% in 1990 to about 17% in 2016, but it remains a major source of employment. According to OECD data, 85% of operational land holdings are less than 2 hectares and account for 45% of the total cropped area. Only 5% of farmers work on land holding larger than 4 hectares, according to the Agricultural Census, 2016. Productivity lags other Asian economies such as China, Vietnam and Thailand and average yields are low compared to other global producers. Wheat and rice yields are nearly 3 times lower than world yields while those for mango, banana, onion or potato are between 2 and 7 times lower than the highest yields achieved globally, according to the OECD

कौटिल्य एकेडमी

क्या हो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा

ऋतु सारस्वत
समाजशास्त्री

महिलाओं और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विषयों पर लेखन।

बीते दो दशकों में दुष्कर्म करने वालों में अवयस्कों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके पीछे प्रत्यक्ष रूप में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध अश्लील साइट्स की सहज उपलब्धता का बड़ा हाथ है।

कंप्यूटर और मोबाइल पर इंटरनेट गेम्स खेलना वयस्कों की देखा-देखी बच्चों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता जा रहा है। इटरनेट गेमिंग के नाम पर क्या खेला जा रहा है और किस-किस किस्म की सामग्री देखी जा रही है, इस पर कम ही लोगों का ध्यान जा पाता है। इससे न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी इतनी खराब हो रही है कि कई बार उन्हें पुनर्वास केंद्र भी भेजना पड़ जाता है।

पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाते हुए अश्लील सामग्री दिखाने वाली लगभग 800 साइट्स को बंद करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 2015 में उच्चतम न्यायालय ने, अश्लील साइट्स को बंद करने के संबंध में केंद्र से जवाब तलब किया था। उस समय सरकार ने 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' पर रोक लगाने की सहमति दिखाई थी, पर सिविल लिबर्टीज और तमाम संगठनों ने यह कहते हुए इस कदम का विरोध शुरू कर दिया था कि किसी वयस्क को एकांत में पोर्नोग्राफी देखने से कैसे रोका जा सकता है। पर क्या यह व्यक्तिगत स्वंतत्रता का प्रश्न मात्र भर है? क्या इंटरनेट को इस्तेमाल करने वालों को सीमित किया जा सकता है? वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह सिर्फ वयस्कों की पहुंच तक रहे और बच्चों के क्लिक करने पर ऐसी साइट्स न खुलें। ऐसी स्थिति में कैसे अश्लील वेबसाइट्स को चलाना उचित है।

निश्चित ही बच्चों तक उनकी पहुंच अप्राकृतिक है और जो अप्राकृतिक है, वह घातक और विकृत है। हमें इस तथ्य को तार्किक रूप से समझना होगा कि बच्चे जो कुछ देखते और सुनते हैं वे उससे प्रेरित होते हैं, बिना यह समझे कि वह उचित है या अनुचित।

मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बैंडोरा ने वर्ष 1961 में, कुछ बच्चों को एक व्यक्ति को हवा भरी गुड़िया को पीटते दिखाया था और फिर इन बच्चों को इसी तरह की गुड़िया दे दी गई, अल्बर्ट ने पाया कि बच्चों ने गुड़िया को ठीक उसी तरह पीटा, जैसे वह व्यक्ति पीट रहा था। अमरीकी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रॉबिन मॉर्गन ने 1974 में लिखे अपने एक लेख 'थ्योरी एंड प्रैक्टिस : पोर्नोग्राफी एंड रेप' में लिखा था कि इसी तरह पोर्नोग्राफी का सिद्धांत भी काम करता है जिसे व्यावहारिक-रूप से दुष्कर्म के रूप में अंजाम दिया जाता है।

दुष्कर्म के पीछे, महिलाओं के हाव-भाव और कपड़ों को दोष देने वाली तुच्छ मानसिकता से ग्रस्त लोग, इस प्रश्न का उत्तर कदापि नहीं दे सकते कि 2 या 3 साल की बच्ची या 70 साल की वृद्ध क्यों पशुता का शिकार होती है? इस प्रश्न का उत्तर वे अश्लील साइट्स भी हैं, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत करती हैं।

टेक बेडी नाम के एक अमरीकी सीरियल किलर ने 30 से अधिक महिलाओं और लड़कियों से वीभत्स तरीके से दुष्कर्म किया और उनकी हत्या की। जनवरी 1989 में मौत की सजा से एक दिन पहले दिए गए एक विस्तृत साक्षात्कार में बेडी ने कहा था कि यदि 'उसे पोर्न देखने की आदत नहीं पड़ी होती, तो उसने यौन-अपराध नहीं किए होते।' वे लोग जो 'नैतिक पुलिसिंग' की बात करके यह दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि पोर्न साइट्स देखना, व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है, अगर किसी को परेशानी है तो इसे न देखे, उन्हें यह समझना होगा कि जब व्यक्तिगत निर्णय, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो तो उसके संबंध में तार्किक विचार अपेक्षित है।

हमारे मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि जो चीज व्यक्ति बार-बार देखे, पढ़े या सुने, वह उसकी सोचने की शक्ति को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि अनजाने में वह उसे स्वीकार भी करता चला जाता है। इसलिए पोर्न सिनेमा या अन्य डिजिटल माध्यमों से परोसे जाने वाले पोर्न का असर दिमाग पर होता ही है। और यह हमें यौन हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार और प्रेरित करता है और इसकी सत्यता की पुष्टि वे आंकड़े करते हैं, जो बताते हैं कि बीते दो दशकों में दुष्कर्म करने वालों में अवयस्कों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके पीछे प्रत्यक्ष रूप में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध अश्लील साइट्स की सहज उपलब्धता का बड़ा हाथ है। इस तथ्य को समझते हुए, सितंबर में नेपाल ने पोर्न साइट्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत में भी आंशिक ही सही, लेकिन कुछ हद तक पाबंदी का प्रयास तो किया ही गया है।

वे लोग जो 'नैतिक पुलिसिंग' की बात करके यह दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि पोर्न साइट्स देखना, व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है, अगर किसी को परेशानी है तो इसे न देखे, उन्हें यह समझना होगा कि जब व्यक्तिगत निर्णय, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो तो उसके संबंध में तार्किक विचार अपेक्षित है।

कौटिल्य एकेडमी

कमजोर होते रुपए के कारण देश में चिंता का माहौल था, वहीं नीति निर्माण से जुड़े हुए कई महानुभाव यह कहते सुने जा रहे थे कि रुपए का गिरना स्वाभाविक है क्योंकि रुपया पहले से ही जरूरत से ज्यादा मजबूत है।

डॉलर, रुपया और अवमूल्यन के तर्क

अश्विनी महाजन
आर्थिक मामलों के जानकार

दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत में और कमी भी आ सकती है। तेल की कीमत में 1 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट हमारे वार्षिक तेल बिल को 1.5 अरब डॉलर कम कर सकती है। इस प्रकार पिछले एक महीने में 26-27 डॉलर की कमी हमारे तेल बिल में सालाना 40 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी ला सकती है।

पिछले कुछ महीनों से अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी अवमूल्यन हो रहा था। रुपए-डॉलर की विनिमय दर जो अप्रेल 2018 में लगभग 64 रुपए प्रति डॉलर थी और उसने 11 अक्टूबर 2018 तक 74.48 रुपए का स्तर छू लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में रुपया मजबूत होना शुरू हुआ और यह 7 दिसंबर 2018 तक 70.80 रुपए प्रति डॉलर तक आ गया।

एक ओर जहां कमजोर होते रुपए के कारण देश में चिंता का माहौल था वहीं नीति निर्माण से जुड़े हुए कई महानुभाव यह कहते सुने जा रहे थे कि रुपए का गिरना स्वाभाविक है क्योंकि रुपया पहले से ही जरूरत से ज्यादा मजबूत है। उनका यह भी कहना था कि रुपए में मजबूती से देश के निर्यात को नुकसान हो रहा है। रुपए को जरूरत से ज्यादा मजबूत बताते हुए उसे कमजोर करने की वकालत करने वाले इन विशेषज्ञों की राय भी अलग-अलग थी।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष जुलाई 2018 में कह रहे थे कि रुपया 5 से 7 प्रतिशत अधिक मूल्यवान है और कई विशेषज्ञ इसे 15 प्रतिशत तक अधिक मूल्यवान बता रहे थे। कुछ अन्य रिपोर्ट इसे 10 प्रतिशत ज्यादा मूल्यवान बता रही थीं। यह पहली बार नहीं हुआ कि कमजोर होते रुपए के मद्देनजर ये नीति-निर्माता उसे और कमजोर करने की सलाह दे रहे थे।

पिछले लगभग छह महीनों में रुपए की कमजोरी के कई कारण रहे। सबसे पहला कारण यह था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही थीं। गौरतलब है कि भारत अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का लगभग 70 प्रतिशत विदेशों से आयात करता है। यदि ईरान को छोड़ दिया जाए, शेष सभी देशों से इस कच्चे तेल के लिए डॉलरों में भुगतान होता है, जबकि अक्टूबर 2017 में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत मात्र 60 डॉलर प्रति बैरल थी, वह बढ़ते हुए

निराशाजनक यह रहा कि रुपया अस्थायी कारणों से इसलिए कमजोर हो रहा था क्योंकि रिजर्व बैंक ने रुपए के अवमूल्यन के नियंत्रण की जिम्मेवारी नहीं निभाई।

अक्टूबर 2018 तक आते-आते 86 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुकी थी। इसके चलते हमारा तेल का बिल बढ़ता गया और इस कारण से डॉलरों की मांग भी।

रुपए की कमजोरी का एक दूसरा प्रमुख कारण यह था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपने निवेश को भारत से ले जाना शुरू किया। शेयर और बांड मार्केट दोनों में उन्होंने भारी बिकवाली की और विदेशी मुद्रा भारत से बाहर स्थानांतरित करनी शुरू कर दी। इससे भी देश में डॉलर की मांग बढ़ गई। रुपए की कमजोरी का एक तीसरा कारण यह भी रहा कि अमरीका ने कंपनी और वैयक्तिक आयकर में भारी कमी कर दी, जिससे वैश्विक निवेशक अमरीका की ओर आकृष्ट होने लगे। दूसरी ओर अमरीकी फेडरल रिजर्व (अमरीका का केंद्रीय बैंक) ने ब्याज दर में वृद्धि कर दी। इससे वैश्विक निवेशक अमरीका की ओर आकर्षित हुए।

जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का प्रश्न है, वह हमेशा नहीं बढ़ती रहती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि सामान्यतः 'ओपेक' देशों द्वारा आपूर्ति को सीमित कर देने के कारण होती है। आखिरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति बढ़ने से तेल की कीमतें फिर नीचे आ जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत में और कमी भी आ सकती है। तेल की कीमत में 1 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट हमारे वार्षिक तेल बिल को 1.5 अरब डॉलर कम कर सकती है। इस प्रकार पिछले एक महीने में 26-27 डॉलर की कमी हमारे तेल बिल में सालाना 40 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी ला सकती है।

अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत से जो विदेशी मुद्रा बाहर ले जा रहे थे पिछले दिनों यह क्रम भी रुक गया। उन्होंने दुबारा भारत की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। शेयर बाजार में पिछले दिनों की वृद्धि इस बात को इंगित कर रही है। इस प्रकार एक बार फिर से कच्चे तेल की घटती कीमतें और दूसरी ओर पुनः विदेशी निवेशकों का भारत की ओर आकर्षण स्वाभाविक रूप से डॉलरों की मांग को कम कर रहा है और रुपया स्वाभाविक रूप से मजबूत होने लगा है।

समूचे प्रकरण में निराशाजनक यह रहा कि रुपया अस्थायी कारणों से इसलिए कमजोर हो रहा था क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थायी रूप से कमजोर हो रहे रुपए के अवमूल्यन को नियंत्रित करने हेतु अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो यह रहा कि नीति-निर्माण से जुड़े महानुभाव रुपए को और अधिक कमजोर करने की वकालत करने में लगे रहे। जबकि यह स्पष्ट था रुपए में यह कमजोरी भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक कारणों से नहीं, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी निवेशकों के बर्हिगमन जैसे अस्थायी कारणों से हो रही है।

देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ विकास दर बढ़ रही है और महंगाई की दर लगातार घटती जा रही है। विभिन्न नीतिगत सुधारों के कारण देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का स्तर भी लगातार सुधर रहा है। साथ ही कृषि और औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देश के आर्थिक मामलों के सचिव और देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रुपए को और कमजोर करने की वकालत 'रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' के आधार पर अपने तर्क देकर कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि इस आधार पर अर्थशास्त्री एकमत नहीं रहे हैं और यह कारक भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर लागू ही नहीं होता।